साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 25 अप्रैल-01 मई 2022, वर्ष-8, अंक-4

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा- वनवासियों को जंगल का मालिक बनाने वाला मप्र देश का पहला राज्य

जंगल के वनवासियों का 'मंगल'

अरविंद मिश्र। भोपाल

देश में ऐसा पहली बार है, जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज का यह कदम अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को शिवराज सिंह साकार करने का काम कर रहे हैं। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के जंबूरी मैदान में तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में कही।

इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से कहा कि ये जल, जमीन, जंगल आदिवासियों हैं। अब जंगल वनवासी ही बचाएंगे। जंगल वनवासियों को सौंप दिए गए हैं। वन विभाग सिर्फ सहयोग करेगा। जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी, उसका 20 फीसदी वनवासियों को दिया जाएगा। तेंदूपत्ता तुड़वाने के अभी 250 रुपए प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वह बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे। शाह ने मध्यप्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। शाह और मुख्यमंत्री ने वन समितियों का सम्मेलन में हितग्राहियों को तेंदूपत्ता के लाभांश का वितरण किया।

- 26 जिलों के 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया का शुभारंभ
- जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी, उसका 20 फीसदी आदिवासियों को मिलेगा
- तेंदूपत्ता तुड़वाने के 250 रु. से बढ़ाकर अब 300 प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे
- पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का होगा हक

जनजातीय वर्ग को ये सौगातें मिलीं

प्रदेश में अभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को 70 फीसदी बोनस मिलता है। नई घोषणा में पेसा अधिनियम के अनुसार तेंदूपत्ता विक्रय से होने वाले लाभ पर 75 फीसदी संग्राहक को, 10 प्रतिशत राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए, 10 प्रतिशत राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण पर और 5 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी। वन विभाग अब राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि में से 33 प्रतिशत वन समितियों को देगी। समिति आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य कर सकेगी। इससे होने वाली आय वन समिति को मिलेगी।

15 हजार गांवों की आजीविका जंगल

प्रदेश के एक तिहाई गांव वन क्षेत्रों के अंदर या उसके आसपास बसे हैं। इनकी संख्या लगभग 15 हजार है, जिनकी आजीविका जंगल पर आधारित है। 5 हजार वन समितियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए माइक्रो प्लान लाया जाएगा। वन समितियों का गठन ग्राम सभा करेगी। समिति में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार मिलेगा। वनोपज में महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और चिरौंजी प्रमुख है।

सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान को अब प्राकृतिक आपदा होने पर पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है, उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी। मप्र ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। पेसा एक्ट क्रमशः मप्र में लागू किया जाएगा। मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है।

जंगल की कमाई का 20 फीसदी आदिवासियों को मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज एक ही बार में 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है, इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। मप्र में 21 फीसदी अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक जनजातीय भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होता, प्रदेश का कल्याण नहीं होता। पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 फीसदी हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। दस साल में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि मप्र ने की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजातीय वर्ग के लिए हमने घोषित किए हैं, वे सभी पूरे होंगे। हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा।

भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी

सम्मेलन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम शिरकत की। सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग में हुए आयोजन में शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलेगी, नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है। जो आज के समय की मांग है।

पहले पेट्रोल-डीजल अब खरीफ की तैयारी में जुटे किसानों को एक और झटका

1200 का डीएपी अब 1350 रुपए में मिलेगा

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश में रबी फसल की कटाई समाप्ति पर है। इसी के साथ ही अब खरीफ की तैयारी में कृषि विभाग जुट गया है। इधर, किसानों को भी खरीफ की तैयारी करना है। इसके लिए खाद-बीज की व्यवस्थाएं प्राइवेट एवं शासकीय तौर पर तेजी से जारी है। खासकर खाद को लेकर अग्रिम तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। प्राइवेट दुकानों को भी पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जा चुका, लेकिन इस बार डीएपी व 12.32.16 किसानों को महंगी पड़ने जा रही है। डीएपी पिछले साल तक 1200 में मिल रहा था, जो इस साल 1350 में दिया जाएगा। जबकि 12.32.16 की कीमत 1340 थी जो इस बार 1470 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा यूरिया भी खरीफ की फसल में उपयोग होता है तो इसके दामों में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। किसान लगातार मौसम की मार झेल रहे हैं और कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि से परेशान है। इस बीच खाद के बढ़ते दामों ने उन्हें और भी रुलाना शुरू कर दिया।

...तो किसानों को खेती करना हो जाएगा मुश्किल

किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती आई, लेकिन डीजल, मजदूरी और अब खाद के दाम बढ़ाकर किसानों से खेती की दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। कृषि संबंधी उपयोगी वस्तुओं की कीमतें इसी तरह बढ़ाई जाती रहीं तो किसानों को खेती करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को बढ़ती महंगाई पर नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यही हाल रहा तो किसान बर्बाद हो जाएंगे।

अभी से कृषि विभाग सक्रिय

प्रदेश में खरीफ सीजन की मुख्य फसलों में सोयाबीन, धान, उड़द आदि की बोवनी किसान करते हैं। इन फसलों में यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट की जरूरत किसानों को रहती है। हर वर्ष खाद के लिए किसानों को भारी मशक्कत करना पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति न बने इसके लिए प्रशासन व कृषि विभाग पहले से ही किसानों को खाद की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम भंडारण कर रहा है।

डीएपी की मूल्य वृद्धि का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। पहले से ही सरकार ने पेट्रोल-डीजल में मूल्यवृद्धि कर किसानों को आफत में डाल रखा है और अब किसानों की पहली जरूरत खाद के दाम भी बढ़ा दिए गए। ऐसे में फसल की लागत और अधिक बढ़ जाएगी जबकि महंगाई के अनुपात में किसान की उपज के दाम नहीं बढ़ाए जाते खाद में यह मूल्य वृद्धि वापस ली जाना चाहिए नहीं तो हर स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

लाखन सिंह मीणा, राष्ट्रीय मजदूर महासंघ

भोपाल मंडी बोर्ड मुख्यालय में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा कॉल सेंटर

गेहूं के निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध कराने कॉल सेंटर शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित गेहूं के निर्यात की कार्यवाही को सुगम बनाने की दृष्टि से निर्यातकों एवं व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय में एक कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 18002333474 है। कोई भी व्यापारी या निर्यातक गेहूं निर्यात से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। कॉल सेंटर के प्रभारी अधिकारी के रूप में सहायक संचालक पीयूष शर्मा को नियुक्त किया गया है। जिन के निर्देशन में उक्त कॉल सेंटर कार्य करेगा। डीके नागेन्द्र, अपर संचालक कॉल सेंटर के पर्यवेक्षण प्रभारी अधिकारी रहेंगे।

निर्यातकों की शंका का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित अमले को कॉल सेंटर में तैनात किया गया है। व्यापारी और निर्यातक अधिक से अधिक उक्त सेवा का लाभ लें।

विकास नरवाल, प्रबंध संचालक
राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मप्र

किसानों के तैयार कर रहा आईआईटी इंदौर, बीमार पौधे में करेगा कीटनाशक का छिड़काव

फसलों का सुरक्षा कवच बनेगा 'डाक्टर ड्रोन'

इंदौर। संवाददाता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआइएई) भोपाल ऐसा स्मार्ट ड्रोन बना रहे हैं, जो खेत में फसल के केवल खराब या बीमारी से ग्रस्त पौधों या हिस्सों को पहचानकर उन पर ही कीटनाशक का छिड़काव करेगा। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) और सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें खराब और अच्छे पौधों की पहचान इमेज प्रोसेसिंग तकनीक की मदद से की जाएगी। यह अपनी तरह का पहला ऐसा स्मार्ट ड्रोन होगा जो फसल के अच्छे हिस्सों पर कीटनाशक नहीं छिड़केगा। इससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर रहेगी और कीटनाशक व समय की भी बचत होगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में किसानों को डिजिटल और उच्च प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं से जोड़ने के लिए किसान ड्रोन व रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा बजट में की थी। केंद्र की घोषणा के बाद आईआईटी इंदौर इस क्षेत्र में नवाचार में जुटा है।

ऐसे काम करेगा डाक्टर ड्रोन

एआई और इमेज प्रोसेसिंग तकनीक की मदद से खराब और अच्छी फसल, फलों और सब्जियों के फोटो लेकर एक सर्वर में रखे जाएंगे। इसके आधार पर ड्रोन में लगे सेंसर खेत में कीटनाशक छिड़काव से पहले फसल के केवल उन हिस्सों की पहचान कर लेंगे जिनमें कीट लग गए हैं या किसी तरह का रोग है।

आईआईटी के पास वेगा ड्रोन

आईआईटी इंदौर के पास ऐसा ड्रोन भी है जिसे देश में ही विकसित पहले माइक्रोप्रोसेसर वेगा से तैयार किया गया है। वेगा सी-डैक (सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) बेंगलुरु ने तैयार किया है। इससे भारत स्व-विकसित माइक्रोप्रोसेसर से ड्रोन बनाने में सक्षम हो गया है। कृषि क्षेत्र के लिए तैयार की जा रही तकनीकों में भी संस्थान इस ड्रोन का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है।

विभिन्न फसलों और फलों में 20 से 30 प्रतिशत तक कीट लग जाते हैं। इससे बचाव के लिए पूरी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती है। कीटनाशक के अपने नुकसान हैं। प्रदेश में पहली बार इस तरह की तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाएगा।

डॉ.सीआर मेहता, निदेशक, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल

पूरी तरह स्वचालित इस ड्रोन को संचालित करना आसान होगा। महज कुछ बटन की सहायता से किसान सहजता से इसका उपयोग कर सकेंगे। इसी वर्ष इसे तैयार कर सीआईएई को सौंपा जाएगा। वह इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित करेगा। इस संबंध में दोनों संस्थानों में चर्चा हो चुकी है।

प्रो.डॉ. शैबल मुखर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी इंदौर

आधार से लिंक खाते में भुगतान की नई व्यवस्था बनाने से विलंब

समर्थन पर किसानों ने 20 लाख टन गेहूं बेचा पर नहीं हो पाया भुगतान

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश में अभी तक ढाई लाख से ज्यादा किसान बीस लाख टन से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं पर भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इससे किसान परेशान हैं, क्योंकि वे न तो सहकारी समितियों का ऋण चुका पा रहे हैं और न ही अन्य जरूरी काम ही कर पा रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग भी किसानों की समस्या को समझ रहा है और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। दरअसल, इस बार भुगतान की व्यवस्था बदली गई है। अब किसान से खाता नंबर लेने की जगह उससे सिर्फ आधार नंबर लिया गया है। इससे लिंक खाते में भुगतान किया जाना है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। तकनीकी प्रक्रिया के कारण इसमें विलंब हुआ है। अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है।

800 करोड़ खाते में डालेंगे

नए साफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान होना है। इसे भी प्रायोगिक तौर पर संचालित करके देख लिया गया है। अब भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पहले एक-एक रुपए खातों में जमा करके देखेंगे ताकि यह पता चल जाए कि राशि पहुंच रही है या नहीं। यदि राशि नहीं पहुंचेगी तो साफ्टवेयर के माध्यम से ही पता चल जाएगा। जिस किसान का खाता संचालित नहीं होगा, उससे संपर्क करके त्रुटि को दूर कराया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर एक हजार 800 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में करने की तैयारी है।

...तो किसान हो जाएंगे डिफाल्टर

भोपाल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय तिवारी का कहना है कि भुगतान में विलंब का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल, किसान सहकारी समितियों से अल्पावधि कृषि ऋण लेते हैं। जैसे ही उपज बिकती है तो वे उससे प्राप्त राशि का ऋण चुकाते हैं। इसके बाद उन्हें फिर से ऋण लेने के लिए पात्रता मिल जाती है और स्वीकृत साख सीमा के अनुसार ऋण ले लेते हैं। यही व्यवस्था चलती रहती है पर भुगतान न होने से यह प्रभावित हो रही है। इसे किसान डिफाल्टर हो जाएंगे।

दस दिन में सरकार को करना था भुगतान

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के दस दिन के भीतर भुगतान करने का दावा किया था, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन की वजह से यह पूरा नहीं हो पाया। सरकार ने उपार्जन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार आधार से लिंक खाते में ही भुगतान करने की व्यवस्था लागू की है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को आधार से लिंक खातों की जानकारी केंद्र सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीए) से लेनी पड़ रही है।

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्डधारी उसी कार्ड से बेचेंगे महुआ फूल

प्रदेश में महुआ फूल 36 रुपए किलो समर्थन मूल्य पर बिकेगा

भोपाल। संवाददाता

महुआ फूल के लिए आर्थिक रूप से निर्भर किसानों के लिए अच्छी खबर है। महुआ फूल की बिक्री के लिए अब उन्हें समर्थन मूल्य के साथ ही बोनस राशि भी मिलेगी। प्रदेश में महुआ फूल की खरीदी के लिए कई जगह फण (खरीदी केंद्र) बनाए गए हैं। वन विभाग द्वारा वन समितियों के माध्यम से संग्राहकों को खरीदी केंद्र में महुआ फूल बिक्री के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, ताकि उन्हें बोनस का लाभ प्राप्त हो सके। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तेंदूपत्ता संग्रहण कार्डधारी उसी कार्ड से महुआ फूल की बिक्री निर्धारित फणों पर कर सकते हैं। बताया गया कि महुआ फूल खरीदी के लिए फण (खरीदी केंद्र) बनाए गए हैं, जिससे संग्राहकों महुआ फूल की बिक्री के लिए ज्यादा दूरी तय करने में परेशानी न उठाना पड़े। फणों के माध्यम से सरकार द्वारा महुआ फूल की खरीदी की जाएगी, इसके बाद उसका विक्रय किया जाएगा, और विक्रय में लाभांस के आधार पर तेंदूपत्ता बोनस की तरह महुआ फूल का भी बोनस वितरित किया जाएगा।

बिचौलियों पर भी होगी कार्रवाई

महुआ फूल खरीदी के लिए ग्रामीण अंचलों में सक्रिय बिचौलिये पर कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महुआ फूल खरीदी के लिए जैव विविधता बोर्ड से पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के महुआ फूल खरीदी करने के वालों के विरुद्ध वन विभाग द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

भोपाल जिले में दस फीसदी ही हो रही सब्जी की खेती

200 नींबू, 150 धनिया पत्ती और हरी मिर्च 120 रुपए किलो

भोपाल। डीजल के बढ़ते दाम और गर्मी का असर सब्जी के दामों पर पड़ा है। सब्जियों की आवक भी बाहर से हो रही है। जिले में 10 फीसदी ही सब्जियों की खेती हो रही है। यहां तक आलू और प्याज भी बाहर से आ रहा है। उसके बाद भी उद्यानिकी विभाग द्वारा नकद की खेती करवाने के लिए किसानों को जागरुक नहीं कर पा रहा है। सब्जियों के भाव 60 रुपए किलो और नीबू 200 रुपए किलो पर पहुंच गया है। ग्राहक रविंद्र घोष, नीलेश घोष, राजू अहिरवार ने बताया कि प्रतिदिन की मजदूरी गृहस्थी चलाने लायक ही हो रही है। जितनी मजदूरी एक दिन में मिलती है, उतना खर्चा पेट्रोल, सब्जी और राशन में हो रहा है। खाद सामग्री से लेकर हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए है। बाजार में 500 रुपए लेकर जाना पड़ रहा है। वापस होने पर कुछ ही छुट्टे रुपए बचकर आ रहे हैं। अब परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। काम भी प्रतिदिन नहीं मिलता है।

पालक 50 रुपए किलो

दुकानदार राकेश कुशवाहा का कहना है कि महंगे डीजल के कारण सब्जी की महंगाई बढ़ गई है। टीकमगढ़ में हाल में 5 फीसदी भिंड़ी, प्याज, कद्दू, मूली, लोकी के साथ कुछ अन्य सब्जियां आने लगी है। लेकिन सभी प्रकार की सब्जियां बाहर से आ रही हैं। पालक भी 50 रुपए किलो फुटकर दुकानों पर मिल रही है। दुकानदारों का कहना था कि ग्वालियर, झांसी, लखनऊ, जबलपुर, इंदौर, बैंगलूरु, हैदराबाद के साथ अन्य महानगरों और प्रदेशों के अन्य जिले से सब्जियां आ रही हैं।

पशुपालन विभाग अब पूरे मध्यप्रदेश में लागू करेगा टेक्निक

भोपाल में एंब्रियो ट्रांसफर से 300 बछड़े-बछिया हुए पैदा

भोपाल। संवाददाता

राजधानी में एंब्रियो (भ्रूण) ट्रांसफर टेक्निक (ईटीटी) से अब तक 300 से ज्यादा दुधारू गाय और स्वस्थ्य बैल पैदा हुए हैं। इनसे न केवल दूध का उत्पादन बढ़ा है, बल्कि बैल के सीमन का उपयोग स्वस्थ्य मवेशी पैदा करने में किया जा रहा है। पशुपालन विभाग अब पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर इसे लागू करने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को प्रोजक्ट बनाकर भी दिया गया है। इसमें 194 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है।

एंब्रेयो ट्रासंफर टेक्निक में एक डोनर मदर होती है। इस मदर से एक बार में 4 से 15 एंब्रियो तैयार होते हैं। इसके बाद एंब्रियो की संख्या के आधार पर इन्हें उतनी ही गायों (सेरोगेट मदर) में ट्रासंफर किया जाता है। इस तरह से अन्य गायें गर्भवती हो जाती हैं और स्वस्थ्य बच्चे को जन्म देती हैं।

ऐसे काम करती है तकनीक

ईटीटी में स्वस्थ्य गाय और सांड चुने जाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली गाय का ओवा लेते हैं और सुपर ओवेल्यूशन करते हैं। डोनर गाय में सांड का सीमन इंजेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (एआई) के सातवें दिन एंब्रियो को कलेक्ट कर इसे सेरोगेट गाय में ट्रांसफर करते हैं। ये गाय स्वस्थ्य बच्चे को जन्म देती हैं।

14-15 लीटर दूध देती है गाय

आमतौर पर एक गाय जहां पांच-छह लीटर दूध भी नहीं देती वहीं ईटीटी से पैदा गाय 14-15 लीटर तक दूध देती हैं। इससे नस्ल सुधार होता है। इस तकनीक से पैदा बछिया या बछड़े में शत-प्रतिशत गुण आते हैं। इस तरह के प्रयोग ब्राजील में खूब हुए हैं। जिस गाय को लोग अनुपयोगी समझकर छोड़ देते हैं वे इस तकनीक में उपयोग में लाई जा रही हैं।

यह टेक्निक वर्तमान में भोपाल में उपयोग में लाई जा रही है। अब इसे प्रदेश भर में संभाग स्तर पर लागू करेंगे। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और नस्ल सुधार होगा। इस तकनीक में डोनर गाय और बुल एक बार उपयोग के बाद फ्री हो जाते हैं। तीन-तीन माह के गैप में इनका फिर से उपयोग किया जाता है। इसमें गिर, साहीवाल आदि नस्लों का उपयोग करते हैं।

-डॉ. एचबीएस भदौरिया, एमडी, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

जबलपुर, सीहोर की जमीन गौ संवर्धन बोर्ड को मिली

गौसदनों के नाम दर्ज 6700 एकड़ जमीन होगी विकसित

प्रदेश में बनेंगे आठ गौवंश वन विहार

- काम शुरू करने की तैयारी, छह जिलों में प्रक्रिया जारी
- सागर जिले के देवल में 3600 एकड़ जमीन गौसदन के नाम
- जबलपुर के कुंडम तहसील में 530 एकड़ जमीन गौसदन की
- सीहोर के देलावाड़ी जंगल में 35 एकड़ जमीन गौसदन
- टीकमगढ़,पन्ना, शिवपुरी, खरगोन और मंदसौर में गौ-सदन की है जमीन

भोपाल। विशेष संवाददाता

मध्यप्रदेश में गौ-सदनों के नाम पर 6700 एकड़ जमीन कागजों पर दर्ज तो है, लेकिन यहां गौ-सदनों का संचालन नहीं हो रहा है। अब गौ संवर्धन बोर्ड इस जमीन पर आठ गौवंश वन विहार बनाने की तैयारी कर रहा है।

जबलपुर और सीहोर में इसके लिए जमीन वन विभाग से पशुपालन बोर्ड को मिल गई है। अन्य छह जिलों में कागजों पर दर्ज जमीन को चिन्हित कर बोर्ड को दिए जाने पर काम शुरू होगा। इनके बनने से फायदा यह होगा कि बेसहारा गायों को यहां पर रखा जा सकेगा। हर गौवंश वन विहार में पांच सौ एकड़ से ज्यादा जमीन होगी। यहां गाय चर भी सकेंगी। साथ ही शेल्टर होम बनाकर उन्हें यहां बांधकर रखा जा सकेगा। इससे गौशालाओं में गौवंश के पशुओं को रखने का दबाव कम होगा।

अंग्रेजों ने बनाई थी गौ-सदन की व्यवस्था

गौ-सदन की व्यवस्था 1916 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। तीन दशक पूर्व तक गौवंश के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में 10 गौ-सदन थे। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के साथ ही दो गौ-सदन रायपुर और बिलासपुर में आ गए। बाद प्रदेश में आठ गौ-सदन बचे, लेकिन जमीनी स्तर पर इनमें खुले मैदान के अतिरिक्त गौवंश को चारा मिलने की व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता या सिर छुपाने की जगह जैसा कुछ नहीं था। इस बीच कई जगहों पर जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। बाद में तत्कालीन कांग्रेस सरकार यानी दिग्विजय सिंह शासन में इन गौ-सदनों को बंद कर दिया। गौ-सदनों की जमीन वन विभाग को दे दी गई थी। अब यह जमीन फिर गौ संवर्धन बोर्ड को मिल रही है।

गौवंश वन विहार बनने से लाभ

प्रदेश में आठ गौ-सदन के गौवंश वन विहार के रूप में विकसित होने से सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को इनमें संरक्षण मिल सकेगा। गौवंश की वजह से सड़कों पर हादसे कम होंगे, जाम नहीं लगेंगे, वाहन चालकों को आसानी होगी। गौवंश का जीवन प्राकृतिक और खुशहाल हो जाएगा। यहां गौवंश के लिए चारा से लेकर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक गौवंश के मान से 20 रुपए प्रतिदिन का बजट तय है, जिससे इन गौवंश के रहने खाने का प्रबंध होगा।

प्रदेश में आठ गौ-सदन हैं, सरकारी रिकॉर्ड में इनके नाम 6700 एकड़ जमीन दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारा प्रयास इन्हें गौवंश वन विहार के रूप में विकिसित करने का है। इनमें से जबलपुर और सीहोर के गौवंश वन विहार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अन्य छह के लिए प्रयास जारी हैं। इनके बनने से प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे तीन लाख से अधिक गयों को यहां संरक्षण एवं सुरक्षा मिलेगी।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, अध्यक्ष, मप्र गौ संवर्धन बोर्ड

ग्राम वन समितियों ने वनों को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए अनूठी मिसाल पेश की

इंदौर की ग्राम वन समिति नाहर झाबुआ ने अवैध कटाई से बचाया दो हजार हेक्टेयर का जंगल

इंदौर। संवाददाता

इंदौर जिले में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित की गई ग्राम वन समितियां बेहतर कार्य कर रही हैं। अनेक ऐसी समितियां हैं जिन्होंने वनों को बढ़ाने और वनों की सुरक्षा के लिए अनूठी मिसाल पेश की हैं। जिले की वन समिति नाहर झाबुआ ने दो हजार हेक्टेयर का वन क्षेत्र बचा रखा है। पहले यहां अवैध कटाई की कई घटनाएं होती थी, मगर अब इन पर रोक लगी है। वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एके श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर जिले में कुल 116 ग्राम वन समितियां वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इनके माध्यम से वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। इंदौर जिले की ग्राम वन समिति शिवनी ने वन क्षेत्र बढ़ाने में बेहतर सहयोग प्रदान किया है। गढ़ी क्षेत्र में लगभग साढ़े 26 हेक्टेयर में 32 हजार 150 पौधे लगाए गए। वन समितियों की लगातार देखभाल से पौधों को जीवित रखने और उन्हें बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके फल स्वरूप लगाए गए पौधों में से लगभग 26 हजार पौधे पूर्ण रूप से जीवित और सुरक्षित हैं। इस तरह पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत 80 से अधिक है। यह उपलब्धि बेहतर मानी जाती है।

हर माह होते थे 10 से 15 प्रकरण

इसी तरह वन क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए नाहर झाबुआ की वन समिति द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में दो हजार से अधिक हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। आज से दस वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में वन को नुकसान पहुंचता था। वनों की अवैध कटाई होती थी। उस वक्त दस से 15 प्रकरण हर माह अवैध कटाई के दर्ज होते थे। वन विभाग के अमले द्वारा वन समिति को सक्रिय किया गया। 35 ग्रामीणों को लेकर वन समिति बनाई गई। इनका बेहतर सहयोग मिलने लगा। इस समिति के वर्तमान में रूप सिंह बानिया अध्यक्ष हैं। वन समिति के सक्रिय सहयोग से प्रकरणों में साल दर साल कमी आती गई। वर्तमान में माह में अब एक या दो ही छोटे-छोटे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। वन समितियों का सहयोग बेहद मददगार साबित हो रहा है।

कुपोषण से लड़ेंगी बायो-फोर्टिफाइड फसलें

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

दुनियां का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी एक जंग कुपोषण के खिलाफ लड़ रहा है। भारत में आज भी कुपोषण की समस्या अत्यंत विकराल है। देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। जिसके कारण देश में हर दूसरी महिला खून की कमी (एनीमिया) से पीड़ित है। साथ ही हर तीसरा बच्चा बौना है। वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में भारत काफी निचले पायदान पर है, जो कि एक चिंता का विषय है।

कुपोषण के खिलाफ इस जंग से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस जंग की अगुआयी कर रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ जंग का हथियार बन रही है बायो-फोर्टिफाइड फसलों की किस्में। केंद्र सरकार चावल का फोर्टिफिकेशन और आम जनता में वितरण की केंद्र पोषित योजना को पूरे देश में लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार के यह प्रयास निश्चित रूप से कुपोषण से लड़ने का एक उपयुक्त हथियार साबित होंगे। भारत में तेजी से देश की जनता को पोषण सुरक्षा देने तथा कुपोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न फसलों की बायो-फोर्टिफाइड किस्मों को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। देश में पिछले कुछ वर्षों तक कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों पर ही ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अब कुछ वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों के द्वारा पोषण, जलवायु अनुकूल, रोग और बीमारियों के प्रति सहनशील प्रजातियों को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही जैव-फोर्टिफाइड फसलों की किस्में रोग, कीट, सूखा, लवणता, बाढ़, जल्दी विकसित होने और यांत्रिक कटाई के लिए सहिष्णु हैं। उच्च पोषण वाली जलवायु अनुकूल किस्में बिना पूरक आहार के किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही मद्दगार साबित होंगी। देश की पोषण सुरक्षा प्राप्त करने तथा कुपोषण को खत्म करने में बायो-फोर्टिफाइड किस्में बहुत महत्व रखती हैं। अब तक देश में चावल, मटर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, क्विनोआ, अरहर, ज्वार की ऐसी 21 किस्में जारी की जा चुकी हैं। बायो-फोर्टिफाइड किस्मों में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिंस जैसे उच्च पौषक तत्व मौजूद होते हैं। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कहना है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी समाधान के रूप में फसलों में बायो-फोर्टिफाइड शुरू किया गया है। फोर्टिफाइड

फसलों की किस्मों से केंद्र सरकार पोषण सुनिश्चित करने जा रही है। बायो-फोर्टिफाइड फसलें भारत की छिपी भूख से लड़ सकती हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों में से एक है। देश में अज्ञात भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2020 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 8 फसलों की 17 बायो-फोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। इसके बाद अब तक विभिन्न फसलों की 21 से अधिक बायो-फोर्टिफाइड किस्में जारी की जा चुकी हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। उच्च जस्ता वाली चावल की किस्में प्रोटीन, आयरन और जस्ता से भरपूर गेहूं की किस्में विकसित हो चुकी हैं। इससे पूर्व गोल्डन राइस विटामिन-ए और बाजरा की जस्ता एवं लोहा से भरपूर मोती किस्म विकसित की जा चुकी हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मक्का, सरसों, मूंगफली, बाजरा, शकरकंद आदि की किस्मों द्वारा भारतीय थाली को पोषक थाली में बदलने की उम्मीद है। हांलाकि इस दिशा में अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। इन किस्मों की पर्याप्त बीज उपलब्धता किसानों के लिए अभी बहुत कम है। देश में अभी भी उच्च सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली फोर्टिफाइड किस्मों का विकास पर्याप्त नहीं हैं। करंट डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार बीमारियों के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते भारत को सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। वैश्विक भूख सूचकांक-2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94 वें स्थान पर था। देश में आज भी लगभग 14 फीसदी आबादी कुपोषित है। भारत में स्टंटिग दर 37.4 प्रतिशत और बच्चों के बीच वेस्टिंग दर 17.3 प्रतिशत सबसे अधिक है। वेस्टिग का अर्थ जिन बच्चों का बजन उनकी लंबाई की तुलना में कम होता है, जो तीव्र अल्प पोषण को दर्शाता है। स्टंटिग का अर्थ जिन बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम होती है, जो कि पुराने कुपोषण को दर्शाता है। भारत सरकार आम आदमी के कुपोषण का मर्ज मिटाने के लिए बायो-फोर्टिफाइड किस्मों के इतर फोर्टिफाइड चावल को लेकर आ रही है। गत वर्ष स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से इसका एलान किया गया था। सामांय चावल में पौषक तत्व मिलाने से चावल फोर्टिफाइड हो जाता है। अतिरिक्त पोषण युक्त चावल तैयार करने के लिए भारत में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए एक्सट्रूजन (बहिर्वेधन) तकनीकी को अपनाया जा रहा है, जो कि सबसे बेहतर तकनीकी है। इसमें सबसे पहले सूखे चावल के आटे को सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण में डाला जाता है और फिर पानी मिश्रित कर देते हैं। इससे बने मिश्रण को मशीनों में गर्म कर चावल के आकार के दाने (एफआरके-फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स) तैयार किए जाते हैं। तद्उपरांत दानों को ठंडाकर सुखा लिया जाता है। उपयोग के लिए जूट के बोरों में पैक कर दिया जाता है। इस तकनीकी पर प्रति किलो लगभग 60 पैसा का खर्च आता है। सरकार इस चावल को राशन की दुकानों, मिड डे मील सहित वर्ष 2024 तक पूरे देश में विभिन्न सरकारी योजनाओं में वितरण करके कुपोषण रोकने की ओर अग्रसर है।

विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती

पृथ्वी दिवस पर विशेष

जयसिंह रावत
वरिष्ठ लेखक एवं चिंतक

विश्व के समक्ष आज जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है। मानव जनित क्रिया-कलाप जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। मानव जनित कारणों ने दुनिया के योजनाकारों, सरकारों तथा राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत के संदर्भ में तो जलवायु का महत्व आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में, मौसम विज्ञान संबंधी रिकॉर्ड वर्षा की मात्रा में अधिक परिवर्तन न होते हुए भी वायु तापमान में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले मौसम को ही वहां की जलवायु कहा जाता है।

जलवायु का सीधा अर्थ है कि क्षेत्र विशेष में तापमान, औसतन वर्षा तथा विभिन्न ऋतुओं में हवा के रुख से है। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले मौसम को ही वहां की जलवायु कहा जाता है। जलवायु का सीधा अर्थ है कि क्षेत्र विशेष में तापमान, औसतन वर्षा तथा विभिन्न ऋतुओं में हवा के रुख से है। जलवायु मुख्य रूप से वहां की भौगोलिक संरचना से नियंत्रित होती है फिर भी उस पर मानवीय गतिविधियों का भी काफी प्रभाव पड़ता है। ये सब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से ही संचालित होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका और चीन में वर्ष 2007 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भारत की तुलना में चार गुणा ज्यादा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और रूस के बाद भारत 5वें स्थान पर आता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की नीतियों एवं तत्परता के परिणाम स्वरूप वर्ष 1994 से 2007 की अवधि में उत्सर्जन की तीव्रता में 30 प्रतिशत की कमी आई है। भारत इसी क्रम को जारी रखते हुए उत्सर्जन की तीव्रता में 20-25 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए प्रयत्न शील है। विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन-कार्बन-डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाये रखने के लिए एक तिहाई (1/3) भूमि पर जंगल होने चाहिए। लेकिन आज-कल घने जंगल दुनिया में 20-21 प्रतिशत और भारत में केवल 12-13 प्रतिशत भूमि पर ही रह गए हैं। यद्यपि भारत का वनावरण 21.71 प्रतिशत तक है, लेकिन इसमें खुले वन अधिक हैं। राजस्थान में तो वनों की हालत और भी दयनीय है। वहां 8-9 प्रतिशत भूमि पर ही वन बचे हैं। जब वृक्ष नहीं, वन नहीं तो वन्यजीव भी नहीं बचेंगे। वनों के घटने से अब पक्षी बहुत कम दिखने में आते हैं और रंग-बिरंगी तितलियां तक दुर्लभ होती जा रही हैं। ईंधन के लिए, फर्नीचर के लिए, भारत और कुछ अन्य देशों में शवदाह के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पर्यावरण की जितनी हानि हो रही है, उसका पूरा अनुमान लगाना तो कठिन है, किन्तु यह स्पष्ट है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। भू-जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मिट्टी का अपरदन तथा जैव विविधता का विनाश तेजी से हो रहा है। विदित है कि हमारा वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। जलवायु पर वायुमंडल और जलमंडल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल के इन घटकों में नाइट्रोजनए ऑक्सीजन एवं कार्बनडाई ऑक्साइड का सभी जीवधारियों के जीवन चक्र से सीधा संबंध है। यद्यपि कार्बन-डाई-ऑक्साइड की वायुमंडल में बहुत कम मात्रा पाई जाती है, किन्तु पृथ्वी पर जीवन क्रम को संचालित करने, वायुमंडल की संरचना और उसके घटकों के बीच मात्रात्मक संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से उसकी अहम भूमिका है, क्योंकि प्राणियों के लिए हानिकारक समझी जाने वाली कार्बनडाई ऑक्साइड हरे पेड़-पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बन-डाई-ऑक्साइड, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड, सल्फर-डाई- ऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। वे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, वनस्पतियों का विनाश कर रही हैं तथा प्राणिजगत के लिए घातक सिद्ध हो रही है। मनुष्य में कैंसर, श्वसन संबंधी अनेक रोग, नेत्र रोग, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं। इन सब गतिविधियों का अन्ततोगत्वा जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विनाश को टालने के लिए तत्काल आवश्यकता है कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा में बड़ी कमी लाई जाए। सीएफसीज के वैकल्पिक यौगिक काम में लिए जाए।

जंगल में आग और गांव में बाघ अध्ययन से हल होगी समस्या

प्राणवायु देने वाले जंगल हर वर्ष की तरह इस बार भी जल रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है कि उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर जैसे राज्य और जम्मू और कश्मीर जैसे केंद्र शासित क्षेत्र में जब शीतकाल भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, तभी से जंगलों में आग फैल गई थी। बाघ और आग का आतंक इतना भयानक है कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पूर्व यानी 13 फरवरी को उत्तराखंड के टिहरी जिले में नरेंद्र ब्लॉक के पसर गांव में 54 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपने आंगन में ही बाघ का निवाला बन गया। मार्च के दूसरे सप्ताह में भी उत्तरकाशी के मगन लाल को घर लौटते वक्त बाघ ने मार दिया था। इसी दौरान टिहरी रेंज में सूरत सिंह कुमाई नाम के वन बीट सहायक जंगल में आग बुझाते वक्त काल के गाल में समा गए। आग हर वर्ष किन कारणों से लग रही है। इसको जानने के लिए व्यापक अध्ययन व शोध करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की जा रही है। पिछले चार दशकों से इसी तरह जंगल लगातार जल रहे हैं। हजारों हेक्टेयर प्राकृतिक जंगल के अलावा वे छोटे-छोटे पौधे भी राख बन जाते हैं, जिन्हें उसी साल वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपा गया था। फूलों की घाटी के आसपास के जंगल जलने की खबर भी मिलती है। ऊंचाई की वन संपदा धू-धू कर जल रही है, जिसे बारिश ही बुझा सकती है। यहां स्थिति यह है कि चारों ओर पहाड़ों पर धुंआ ही धुंआ नजर आ रहा है और मैदानों में प्रदूषण का कोहरा पर्यावरण के लिए संकट पैदा कर रहा है। वनाग्नि और वन कटान, दोनों उत्तराखंड के जंगलों में आज-कल चरम सीमा पर है। इससे बारिश में भूस्खलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अनेक घटनाओं से पता चलता है कि हर बार ऊंचाई के जंगल से आग सुलगती है, जो विकराल रूप लेकर गांव तक पहुंच जाती है। इसका दुष्प्रभाव जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। बाघ को जंगल में पर्याप्त भोजन न मिलने से उसने गांव की तरफ रुख कर लिया है। अक्सर समाचार आते हैं कि बाघ ने किसी को अपना निवाला बना लिया है। उत्तरकाशी में जंगल के निकट बसे हुए गांव दिलसौढ़, चामकोट, अठाली, लोदाडा, कमद, अलेथ, मानपुर आदि गांवों के लोग बताते हैं कि आग लगने से हिरन, जंगली सुअर, बारहसिंघा आदि झुलस कर मर रहे हैं। इस प्रजाति के जानवर जंगल में अब दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। इसके कारण गांव में मवेशियों और लोगों को मारने के लिए बाघ पहुंच गया है। देश में बाघों की संख्या पर हर साल जोर दिया जा रहा है, किंतु बाघ के भोजन की व्यवस्था जंगल में हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जंगल के राजा के इस आतंक के साथ-साथ मध्य हिमालय में चौड़ी पत्ती की अनेक वन प्रजातियां जैसे बांझ, बुरांश आदि के जंगल आग से समाप्त हो रहे हैं। चीढ़ की सूखी पत्तियां जंगल में आग फैलाने के लिए अधिक संवेदनशील हैं, लेकिन शंकुधारी चीढ़ के ऊंचे पेड़ों को कम ही नुकसान पहुंचता है। अब यह स्थिति आ गई है कि शीतकाल से ही जंगल जलने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में जंगली जानवर गांव की ओर आने लगते हैं, जिसमें आग के साथ बाघ का डर समाप्त नहीं हो रहा है।

-सुरेश भाई, लेखक सामाजिक कार्यकर्ता

हमारा गेहूं खरीदने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम की लगी कतार

मप्र के गेहूं की विश्व बाजार में बढ़ी मांग

-मिस्र, फिलीपिंस, जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों में भी निर्यात होगा मप्र का अनाज

-प्रदेश से ढाई लाख टन गेहूं हुआ निर्यात, इंदौर से सर्वाधिक 97 हजार टन

भोपाल। प्रशासनिक संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है उसके साकार होने की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मप्र के किसानों का इस समय पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्वभर में मप्र के गेहूं की मांग बढ़ गई है। प्रदेश से अब तक ढाई लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है। यह गुजरात और आंध्रप्रदेश के बंदरगाहों से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम भेजा गया है। इसमें सर्वाधिक 97 हजार 887 टन गेहूं इंदौर से निर्यात किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा और दतिया से व्यापारियों ने गेहूं भेजा है। मिस्र, फिलीपिंस, जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों में भी निर्यात की संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश से कुल पौने दो लाख टन कृषि उपज और उससे जुड़े उत्पाद निर्यात हुए थे। इसमें भी चावल की मात्रा सर्वाधिक एक लाख 27 हजार टन थी।

सीएम स्वयं कर रहे निगरानी

विदेश में बढ़ रही गेहूं की मांग को बड़ा अवसर मानते हुए शिवराज सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। वे प्रति सप्ताह निर्यात की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हैं तो कृषि विभाग ने प्रतिदिन निर्यातक और व्यापारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था बनाई है। इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक ढाई लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश से निर्यात हो चुका है।

किसानों के साथ सरकार को भी फायदा

सरकार का मकसद है कि मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग विदेश में बन जाए, जिससे निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। इसका लाभ किसानों के साथ-साथ सरकार को भी होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक बड़ी कंपनियां मंडियों से गेहूं खरीदकर अपने स्तर पर निर्यात करती थीं। पहली बार सरकार अपने स्तर पर इसे प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मंडी शुल्क में छूट देने के साथ रेलवे की रैक और बंदरगाहों पर स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई है। 26 लाख टन गेहूं के लिए रैक पाइंट पर भंडारण की व्यवस्था बनाई जा चुकी है। अभी तक 87 रैक गेहूं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, विएतनाम भेजा जा चुका है।

भारत को मिला आपदा में अवसर

रूस और यूक्रेन युद्ध से उपजे खाद्य संकट के समाधान के लिए भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। रूस और यूक्रेन दुनिया में गेहूं के निर्यात के मामले में अग्रणी देश हैं लेकिन दोनों के बीच युद्ध ने वैसे देशों के सामने चुनौती पैदा कर दी है जो उनसे गेहूं खरीदते हैं। ऐसे में उन सभी देशों को भारत में संभावनाएं दिख रही हैं। अफ्रीकी देश मिस्र की ओर से भारत के गेहूं को अपने यहां आयात की मंजूरी दिए जाने के बाद अब भारत ने दूसरे देशों में भी गेहूं निर्यात करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जल्दी ही 9 देशों में अपना एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रहा है।

1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य

भारत की ओर से गेहूं निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इन देशों में मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया और लेबनान शामिल हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक संकट से पैदा हुई मांग की बीच भारत ने इस साल (2022-23 के दौरान) कुल 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। एपीडा के चेयरमैन एम अंगमुथु के मुताबिक अकेले मिस्र को 30 लाख टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 तक दुनिया भर में हो रहे गेहूं के व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम रहा था। पिछले साल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए भारत ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था जिसकी कीमत दो बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। हालांकि इसमें से 50 फीसदी गेहूं केवल बंगलादेश को निर्यात किया गया था।

निर्यात के लिए विभिन्न कंपनियों ने दो हजार से ज्यादा रेलवे रैक के लिए मांग पत्र भेजे हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोजांबिक और जिम्बाब्वे के आयोजकों को गेहूं के लागत पत्रक भी भेज दिए हैं।

बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री

देश में सबसे अधिक इंदौर जिले में आलू का उत्पादन

गेहूं के साथ मप्र का शुगर फ्री आलू भी विदेशों में लोकप्रिय

भोपाल। संवाददाता

पिछले दो साल में 98 हजार मैट्रिक टन गेहूं विदेशों को निर्यात करने वाले मप्र का आलू भी खासा लोकप्रिय है। मप्र के गेहूं को मिस्र की जनता भी खाएगी। वहीं शुगर फ्री आलू की भी मांग लगातार देश-विदेश में बढ़ रही है। देश का प्रमुख आलू उत्पादक जिला होने से इंदौर में एक जिला-एक उत्पात योजना में आलू का चयन किया गया है। हर साल 45 हजार हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन किया जा रहा है। चिप्स, पापड़, टिक्की, फ्रेंच फ्राइज से लेकर अन्य खाद्य सामग्री में इंदौरी आलू का चलन बढ़ गया है। आय-वर्धक होने के कारण किसान बड़ी संख्या में आलू उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुगर-फ्री आलू की चिप्स तलने के बाद लाल नहीं होती, सफेद बनी रहती है। आलू उत्पादन के लिए जिले में किसानों को 25 से 35 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान पर आलू फसल आधारित नवीन सूक्ष्म उद्योग लगाने की ओर युवा वर्ग प्रेरित हो रहा है।

एक हेक्टेयर में 240 क्विंटल

इंदौरी आलू की विशेषताओं के चलते अनेक छोटी कंपनियों के साथ प्रतिष्ठित कंपनियों ने भी इंदौर में कारखाने स्थापित किए हैं। आमतौर पर एक हेक्टेयर में 220 में 240 क्विंटल तक आलू का उत्पादन होता है, लेकिन देपालपुर तहसील के ग्राम चितोड़ा के किसान भरत पटेल ने उन्नत तकनीक अपनाई।

प्रदेश में तीस जून तक निर्यातकों को सुविधा

गेहूं का निर्यात पर मंडी शुल्क में छूट

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गेहूं के निर्यातकों को मंडी शुल्क में छूट देगी। अभी सौ रुपए की उपज खरीदने पर डेढ़ रुपए शुल्क देना होता है। इस राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्यातक को की जाएगी। यह सुविधा एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक किसानों से खरीदे गए गेहूं में से 31 मार्च 2023 तक निर्यात की मात्रा पर मिलेगी। निर्यातक का मंडी बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। वो जो भी उपज खरीदेगा, उसे ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात करने के बाद 60 दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। विदेश में गेहूं की बढ़ती मांग को अवसर के रूप में लेते हुए प्रदेश सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार केंद्रीय मंत्रियों और निर्यातकों के साथ बैठक कर चुके हैं।

निर्यातक का मंडी बोर्ड में पंजीकृत अनिवार्य

अब नहीं होगी गड़बड़ी

यह प्रावधान किया गया है कि मंडी शुल्क से छूट केवल मध्य प्रदेश से खरीदे गए गेहूं पर मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए निर्यातक का मंडी बोर्ड में न सिर्फ पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है, बल्कि उसे ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उपज की मात्रा अपने खाते में दर्ज करनी होगी।

निर्यातकों को दो माह के अंदर करना होगा आवेदन

निर्यातक पहले मंडी शुल्क का भुगतान संबंधित कृषि उपज मंडी में करेगा और फिर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात करने के बाद 60 दिन के भीतर आवेदन देगा। आवेदन का निराकरण तीस दिन के भीतर किया जाएगा। यदि निर्यात को लेकर जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो मंडी अधिनियम के तहत लायसेंस निरस्त करने के साथ प्रतिपूर्ति की राशि 24 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली जाएगी।

श्योपुर बनेगा संभाग में दुग्ध केंद्र, दिल्ली तक होगी सप्लाई, जून से शुरू होगा प्लांट

गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति शिवपुरी की हुई बैठक

शिवपुरी गौशाला और श्योपुर दूध में होगा आत्मनिर्भर

दुग्ध उत्पादक किसानों को रोजाना तीन लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा

खेमराज मौर्य। शिवपुरी/श्योपुर

मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनाने के लिए सरकार जुटी हुई है। इसी कड़ी में शिवपुरी और श्योपुर को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल, श्योपुर के कराहल में 50 गांवों के 5 हजार दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन इकाई का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दो करोड़ रुपए की अनुदान राशि मंजूर की है। इसमें 2 ब्लक दुग्ध कूलर रहेंगे। जिनकी क्षमता 8 हजार लीटर दूध स्टोरेज करने की होगी। इसमें दुग्ध उत्पादक किसानों को रोजाना तीन लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट मप्र डे आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के द्वारा किया जाएगा। संभवत: एक जून से दुग्ध प्लांट शुरू हो जाएगा। इधर, शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति शिवपुरी की बैठक गत दिनों जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न गौशालाओं के संचालन में आ रही समस्याओं को समस्त उपस्थित गौशाला संचालकों द्वारा व्यक्त किया गया। कलेक्टर ने सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसी तारतम्य में गौशाला संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में भूसा कारोबारियों द्वारा भूसे का अवैध स्टॉक कर कालाबाजारी की जा रही है जिससे भूसे के दाम अत्यधिक बढ़ रहे हैं। जिससे गौ शालाएं भूसा क्रय नहीं कर पा रही हैं। गौशालाओं को न्यूनतम दर पर भूसा व्यापारियों से भूसा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा जिले से बाहर भूसे के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

श्योपुर का मावा शुद्धता का ब्रांड- श्योपुर जिले के जंगल में बसे एक गांव गोरस का दूध और मावा अपने आप में शुद्धता का ब्रांड है। इस विश्वास की वजह गुर्जर मारवाड़ी समाज की यह मान्यता है कि दूध के धंधे में मिलावट करने से पशुधन नहीं बढ़ता है। गोरस से दूध श्योपुर व राजस्थान के कोटा, बारां व सवाई माधौपुर तक जा रहा है।

कराहल में गिर नस्ल की गाय| गिर नस्ल की गाय प्रदेश में श्योपुर के कराहल में हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद गोरस गांव में है। गिर गाय की नस्ल सुधार के लिए यहां ब्रीडिंग फॉर्म खोला जा रहा है। गौवंश सिर्फ कराहल क्षेत्र में है। यहीं का दूध व मावा जिले के साथ आस-पास के राज्यों में भी प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर शिवपुरी-पाली हाइवे पर सीप नदी के पास बसे इस गांव में 800 घर हैं। इनमें गुर्जर मारवाड़ी समाज के 250 परिवार गाय-भैंस पालते हैं। हर परिवार के पास 100 से 300 गाय हैं।

सिलपुरी में बन रहा दुग्ध केंद्र| गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है। इसके लिए सिलपुरी में बिल्डिंग तैयार की जा रही है। लगभग काम भी पूरा हो चुका है, अब फिनिसिंग का काम चल रहा है। मई माह के लास्ट तक भवन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद दुध का प्लांट लगया जाएगा। 2 से 4 दिन में लगकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद 1 जून से केंद्र पर दुग्ध की खरीदी शुरू कर दी जाएगी।

मऊ की महिलाएं करेंगी दूध की खरीदी| आजीविका मिशन से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं इस प्लांट पर दूध की खरीदी करेंगी। प्रतिदिन महिलाएं दुध खरीद कर दिल्ली भेजेंगी। गाय के दूध के साथ भैंस का दूध भी खरीदी जाएगा। दोनों दूध को अलग-अलग रखा जाएगा। दूध को खरीदने के बाद भारत सरकार से संबंधित मदर दूध डेयरी दिल्ली भेजा जाएगा। महिलाएं पशु पालकों से खरीदे गए दूध का भुगतान हर सात दिन में करेंगी।

ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा| गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है, जिसे लेकर हरियाणा के करनाल से दल ने गायों को देखा और इनके दूध की भी जांच की। गिर नस्ल की गाय प्रदेश में श्योपुर के कराहल में है, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद गोरस गांव में है। इस नस्ल को लेकर क्षेत्रीय सांसद व अन्य कई जनप्रतिनिधि पहले भी कई योजनाएं चलाने की घोषणाएं कर चुके हैं। अब गिर गाय की नस्ल सुधार के लिए यहां ब्रीडिंग फॉर्म खोला जा रहा है।

- शिवपूरी की गौशालाओं को चारे-भूसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। भूसे की कालाबाजारी अगर कोई करेगा और भूसा व्यापारी नियम विरुद्ध स्टॉक करता है या अवैध रूप से भूसा निर्यात करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

  अक्षय कुमार सिंह
  कलेक्टर, शिवपुरी

- कराहल के सिलपुरी गांव में मिल्क सेंटर खोला जा रहा है। इसके लिए भवन बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही मशीने लग जाएगीं तो दूध की खरीदी शुरू हो जाएगी। स्व-सहायता समूह की महिलाएं इस प्लांट को मिलकर चलाएंगी।

  डॉ. एसके मुदगल
  डीपीएम, श्योपुर

सेहतमंद गिर का गाय का दूध

हरियाणा के करनाल से आए दल ने गायों को देखा और इनके दूध को भी जांचा। जिसमें ए 2 विटामिन पाया गया है। यह विटामिन मानव शरीर के लिए सेहतमंद है, इसमें शरीर के लिए काफी पौष्टिक बताया गया है जो कि सिर्फ देसी यानी गिर नस्ल की गायों में ही पाया जाता है। वैज्ञानिकों व पशुपालन विभाग के अनुसार यह पीलापन ही दूध की ताकत है, जिसे गिर गाय सूरज यानी धूप से खींचती है और इसी कारण यह दूध पीला होने के साथ पौष्टिक भी होता है।

मधुमक्खी का पालन फलों में उत्पादकता के लिए वरदान

कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठता डॉ. पयासी बोले

रीवा। फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया, कृषि महाविद्यालय रीवा में स्थापित मधुमक्खी पालन इकाई का उद्घाटन प्रो. एसके पयासी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा किया गया। प्रो. पयासी ने बताया कि फलों में मधुमक्खी के द्वारा परागण होने से फलों में उत्पादकता के साथ-साथ गुणवत्ता में भी काफी सुधार होता है। मधुमक्खी पालन अपनाने से कृषि के साथ किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है। जो किसानों के आय लक्ष्य को दोगुना करने में सहायक हो सकता है। फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया रीवा में कार्यरत वैज्ञानिक डॉ. यूएस बोस, डॉ. टीके सिंह, सुधीर सिंह के प्रयास एवं डॉ. अखिलेश कुमार मधुमक्खी विषैषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के मार्गदर्शन में इस इकाई की स्थापना हुई, जो भविष्य में आम, अमरूद, आंवला, करौंदा, कटहल और नीबू के फलों की उत्पादकता व गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। जिससे जिले के साथ-साथ प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। महाविद्यालय के प्रो. एसके त्रिपाठी, प्रो. आरपी जोशी, डॉ. अखिलेश कुमार वैज्ञानिक ने मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया की मधुमक्खी पालन व्यवसाय भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर गौरव नामदेव के साथ-साथ प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।

मंडला और दमोहः सफलता की कहानी

वन ग्राम समिति की मेहनत से लौट रहा वनों का खोया वैभव

मंडला/दमोह। संवाददाता

वन विभाग ने माइक्रो प्लानिंग कर ग्राम वन समितियों के सहयोग से जंगलों की बहाली पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। मंडला जिले का मनेरी वन ग्राम स्टाक मेपिंग (वर्ष 2004-14) क्षेत्र वनस्पति से रहित था और आरडीएफ (वन पुनर्घनत्वीकरण) के लिए चुना गया था। मनेरी ग्राम वन समिति का गठन कर उसे 186.92 हेक्टेयर वन प्रबंधन का काम सौंपा गया था। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होने के कारण यह वन क्षेत्र गंभीर जैविक दबाव में था। बावजूद इसके स्थानीय समुदायों ने अवैध कटाई और चराई के खिलाफ वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2003-4 और 2005-6 के बीच यहां जंगल बहाली का काम शुरू हुआ। इस काम में ग्राम वन समिति मनेरी का नेतृत्व कर रही महिला सुश्री कल्लू बाई मार्को ने वन संरक्षण और प्रबंधन के लिये समुदाय को संगठित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। ग्राम वन समुदाय के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प के चलते आज यह क्षेत्र वन से बहाल हो गया है। इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में समुदाय ने 3 हजार 526 सागौन और 31 ईंधन के जर की कटाई कर लाभ भी कमाया है। वन विभाग ने स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन और उनकी बहाली में शामिल करते हुए प्रदेश के खाली वन क्षेत्रों को वन सम्पदा से समृद्ध करने में कामयाबी हासिल की है।

कुलुवा गांव की बंजर जमीन में फैलायी हरियाली

इधर, दमोह जिले में ग्राम कुलुवा की बंजर जमीन अब हरे-भरे पेड़ों से आच्छादित है। यह संभव हुआ है, वन समितियों के दृढ़ निश्चय और सकारात्मक प्रयासों से। समिति के सदस्यों ने न हम पेड़ काटेंगे और न काटने देंगे के संकल्प को पूरी तन्मयता से निभाया। समिति ने तय किया है कि कोई भी पेड़ काटेगा तो 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साइकिल पर पेड़ काटकर ले जाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और साइकिल जब्त कर समिति उसकी नीलामी की जाएगी। ग्राम वन समिति में पूर्व अध्यक्ष रूपलाल मिश्रा ने बताया कि जब मैं सरपंच बना तो, क्षेत्र का सर्वे करवाया। सर्वे में 3668 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गयी। फिर ग्रामीणों के साथ राय-मशविरा कर पौधे लगाने और पेड़ों के बचाने की रूपरेखा बनी। सर्वसहमति से बनी रूपरेखा का क्रियान्वयन करने के लिए 12 समितियाँ गठित की गयी। समितियों ने सर्वप्रथम 40 हेक्टेयर में मिश्रित प्लांटेशन किया। इसके बाद यह क्रम लगातार जारी रहा। प्लांटेशन के लिए गड्ढा खोदने, फेंसिंग करने आदि कार्यों में ग्रामीणों को लगाया गया, जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त हुआ। कुलुवा में पदस्थ बीट गार्ड पवन सिंह ठाकुर ने बताया कि यहां पर 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन है। पेड़ों की कई प्रजातियां लगाई गई हैं और मिश्रित वृक्षारोपण हैं। आंवला, शीशम, नीम, सागौन, करंज, खामेर, महुआ, कोहा, जामुन एवं अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। यहां पर हरियाली के कारण जंगली सूअर, छिकरा, हिरण, खरगोश एवं नीलगाय विचरण करती देखी जा सकती हैं।

2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य-3280, तिलहन का 413.4 लाख टन निर्धारित किया टारगेट

किसानों को बीज-खाद उपलब्ध कराएंगे केंद्र और राज्य

भोपाल। संवाददाता

देश में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों तक जरूरी जानकारी व खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ अभियान-2022 की शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि के लिए खरीफ अभियान 2022-23 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के जरिए फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती फसल सीजनों के दौरान फसल निष्पादन की समीक्षा व आकलन करना और राज्य सरकारों के परामर्श के साथ खरीफ सीजन के लिए फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना, महत्वपूर्ण इनपुटों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों को किसान की पहुंच में लाना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि द्वितीय अग्रिम आकलनों (2021-22) के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3160 लाख टन अनुमानित है जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड होगा। दलहन और तिलहन का उत्पादन क्रमश: 269.5 और371.5 लाख टन होगा। तृतीय अग्रिम आकलनों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बागवानी उत्पादन 3310.5 लाख टन होगा जो भारतीय बागवानी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक है।

प्राकृतिक-जैविक खेती पर जोर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए इनपुट लागतों में कमी लाने के लिए केंद्र व राज्य कीटनाशकों और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिल कर काम करेंगे। सरकार को प्राकृतिक और जैविक कृषि पर जोर देना जारी रखना चाहिए। जहां कृषि निर्यातों में बढोतरी हुई है, गुणवत्ता उत्पादों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। निर्यातकों और किसानों दोनों को लाभ पहुंचना चाहिए।

पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य तय

सम्मेलन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न का राष्ट्रीय लक्ष्य चालू वर्ष के दौरान 3160 लाख टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में 3280 लाख टन तय किया गया है। दलहन और तिलहन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न का राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमश: 295.5 लाख टन व 413.4 लाख टन निर्धारित किया गया है। पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 के 115.3 लाख टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 205.0 लाख टन कर दिया गया है।

शोकनगर के किसान में एसी प्लांट में शुरू किया प्रोडक्शन

दोस्त के एक आइडिया से बदल गई किस्मत

मशरूम की खेती ने रजत को किया मसहूर

अशोकनगर। संवाददाता

अशोकनगर जिले के एमबीए पास 27 साल के रजत जैन। बेंगलुरु में एमएनसी में 80 हजार रुपए प्रतिमाह की नौकरी। फिर नौकरी छोड़ी और मिट्टी से जुड़ गए। गांव आकर खेती शुरू कर दी। इसी बीच, दोस्त के आइडिया ने किस्मत बदल दी। दो साल तक ट्रेनिंग और रिसर्च के बाद मशरूम उगाना शुरू किया। आधुनिक तरीके से मशरूम उगाने लगे। अशोकनगर में 4 करोड़ की लागत से मशरूम का एसी प्लांट लगाया। अब रोजाना करीब एक टन मशरूम उगा रहे हैं। मशरूम को दिल्ली, यूपी समेत देशभर के कई राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं। इससे रोजाना एक लाख कमा रहे हैं।

ऐसे आया आइडिया- दियाधरी गांव के रहने वाले रजत जैन ने बेंगलुरु से मार्केटिंग में एमबीए किया। यहीं से कैंपस सिलेक्शन हो गया। कॉलेज के दिनों से ही खुद का बिजनेस करना चाहते थे। जॉब छोड़ अशोकनगर आ गए। यहां 2018 में पहली बार 6 बीघा खेत में टमाटर समेत सब्जी उगाना शुरू किया। प्रॉफिट अच्छा हुआ। रजत ने बताया कि मशरूम की खेती से पहले मैं सब्जी उगा रहा था। हॉर्टिकल्चर पद्धति से टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च और मिर्च उगाई। इस दौरान एक दोस्त ने उन्हें मशरूम की खेती का आइडिया दिया। इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। इंदौर, ग्वालियर सहित कई जगहों पर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन भी गया था।

ऐसी चाहिए जलवायु- बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। बटन मशरूम के लिए 22-25 सेंटीग्रेट तापमान और 80-85 प्रतिशत नमी की जरूरत होती है। बटन खुम्बी की फसल के लिए शुरू में 22-26 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर कवक जाल तेजी से बढ़ता है। बाद में इसके लिए 14-18 डिग्री तापमान ही उपयुक्त रहता है। इससे कम ताप पर फलनकाय की बढ़वार धीमी हो जाती है।

ऐसे उगाते हैं मशरूम

रजत ने बताया कि मशरूम उगाने के 3 स्टेप होते हैं। अपनी बात करूं, तो रूम को तीन भागों में बांटा है। पहले भाग में खाद तैयार की जाती है। इसके बाद मशरूम के बीज तैयार किए जाते हैं। फिर मशरूम उगाया जाता है। अभी हम बाहर से बीज मंगवा रहे हैं। खास है कि इसमें तापमान का भी ध्यान रखा जाता है। एसी का तापमान 20 डिग्री रखा जाता है। तीन दिनों तक भूसे को खुले मैदान में रखकर पानी का छिड़काव करते हैं। बाद में इसे छांव में शिफ्ट किया। यहां सात दिन भूसा पड़ा रहता है। उसके बाद अगली जगह शिफ्ट किया जाता है। जहां जमीन में डली पाइप लाइन से 5 दिन तक गर्म हवा दी जाती है। 5 दिन के बाद इसे पॉलिथीन में पैक करके अंदर ले जाते हैं। प्लांट के अंदर कमरे में मशरूम के बीज मिलाकर तीन दिनों तक पॉलीथिन में बंद करके रखा जाता है। फिर उसे ऊपर से काटकर खोल दिया जाता है। इसके बाद मशरूम उग जाते हैं। करीब 15 दिन बाद कटिंग शुरू हो जाती है।

100 लोगों को दिया रोजगार | रजत का कहना है कि जब मैंने मशरूम उगाने की बात कही, तो परिवारवाले चिंतित हुए। हालांकि, भरोसा दिलाने पर वे सपोर्ट करने लगे। 95 लाख का लोन लिया। इतने पैसे नाकाफी थे। जब परिवार से रुपए लिए, तो उनका डर बढ़ा। क्योंकि यह धंधा चले न चले किसी को पता नहीं था। जैसे ही धीरे-धीरे काम शुरू किया सबकुछ सही हो गया। उन्होंने बताया कि अब करीब 100 लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा चुके हैं।

रोजाना एक टन मशरूम उगाने वाला प्लांट

दो साल पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट में अब तक साढ़े 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 8 महीने पहले ही उत्पादन शुरू हुआ है। शुरुआत में 5 महीने नुकसान हुआ। बीते 4 महीने में लेवल पर आ गया। अभी गर्मी के समय मांग अच्छी है। इस समय कीमत भी दोगुनी हो जाती है। शादी के सीजन में काफी डिमांड रहती है। देशभर में कम जगह पर ही मशरूम के एसी प्लांट हैं। होली के बाद से जुलाई तक मशरूम का मुख्य सीजन होता है। यहां एक टन प्रतिदिन का प्लांट लगाया है। फिलहाल 180 से 220 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं।

पंजाब के प्लांट में मजदूर बनकर सीखा काम

रजत ने बताया कि अशोकनगर या मप्र में मशरूम की खेती को लेकर बड़ा प्लांट नहीं है। पंजाब में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, इसलिए मैं मशरूम की खेती सीखने पंजाब गया। यहां कई जगह मशरूम का उत्पादन देखना चाहा, लेकिन जहां मशरूम का उत्पादन अच्छा होता था, वह तरीका नहीं बताते हैं। रजत को काम सीखने के लिए मजदूर बनकर अंदर जाना पड़ा। वहां में धीरे-धीरे सब कुछ देखा और समझा। कई जगहों पर प्रशिक्षण भी लिया। पूरा काम सीखने में लगभग छह महीने लग गए। अब रजत जिले के अन्य किसानों के लिए आदर्श बन गए हैं।

पर्यावरण प्रेमी बीहड़ में फैला रहे जंगल की हरियाली

कोई सूखे कुएं में पानी सहेजकर तो कोई पौधे लगाकर कर रहा धरती का श्रृंगार

मुरैना। संवाददाता

जंगल की हरियाली, मीलों दूर से नजर आने वाले ऊंचे-ऊंचे चोटीदार पहाड़ और नदियों का कल-कल बहता पानी ही धरती का श्रृंगार है। अगर यह तीनों चीजें न हों तो धरती पर इंसान तो क्या किसी भी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इस अनमोल धरोहर को माफिया उजाड़ने में लगे हैं। पत्थर माफियाओं ने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ गायब कर दिए हैं। लकड़ी और जमीन माफिया जंगल की हरियाली को लील रहे हैं तो रेत माफिया नदियों का अस्तित्व मिटाने पर तुले हैं। धरती की सुंदरता को जर्जर कर रहीं ऐसी लाख बुराइयों के बीच, कई ऐसे पर्यावरण प्रेमी भी हैं, जो हरियाली बढ़ाकर और जलसंरक्षण करके धरती का श्रृंगार करने में बिना किसी स्वार्थ के सालों से जुटे हैं।

शहर से लेकर गांव-गांव में करवा रहे पौधारोपण- मुरैना शहर के अंबाह बायपास के निवासी संदीप शर्मा एलआइसी में विकास अधिकारी हैं। साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती की तैयारी भी करवाते हैं। दो साल पहले उन्होंने सरकारी व निजी जमीनों पर पौधे लगवाना शुरू किए। डेढ़ दशक से कोचिंग चला रहे संदीप शर्मा के शहर से लेकर गांव-गांव में छात्र हैं। इसी नेटवर्क का उन्होंने पौधारोपण में उपयोग किया। हर रविवार को छुट्टी के दिन वह देवरी नर्सरी से खुद के खर्च से 100 पौधे खरीदते हैं। इन्हें कार में रखकर वह बारी-बारी से तीन गांवों में जाते हैं। गांवों में चौपाल लगाकर पहले ग्रामीणों को जल संरक्षण, पौधे लगाने के फायदे बताते हैं, फिर ग्रामीणों से पौधेरोपण में रुचि की जानकारी लेते हैं। वह ऐसे ग्रामीणों का चयन करते हैं जो पौधा लगाकर खुद उसकी नियमित रखवाली करे। 17 अक्टूबर 2021 को तो संदीप शर्मा ने एक ही दिन में 10 हजार पौधे लगवाए। अब तक यह मुरैना नगर निगम के 35 से ज्यादा वार्डों में हजारों से ज्यादा और जिले के 95 गांवों से ज्यादा गांवों में 20 हजार से ज्यादा पौधे लगवा चुके हैं।

रिटायर एसआई बीहड़ों को हरा करने में जुटे

उप्र के रायबरेली जिले की लालगंज तहसील के निवासी 71 साल के रामवरण बैस मुरैना जिले के महुआ थाने में 2008 से 2011 तक एसआइ रहे। 2011 में रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त थानेदार का मन बीहड़ में बने महुआदेव मंदिर पर ऐसा रमा कि बीते 11 साल से वह इस मंदिर के आसपास बीहड़ क्षेत्र में पौधे लगा रहे हैं। अब तक मंदिर परिसर की 26 बीघा जमीन में 60 आम के पेड़, 250 अमरूद के पेड़, आंवला के 40 नीम, जामुन, पीपल आदि के 450 से ज्यादा पौधे लगाए, जिनमें से अधिकांश पेड़ बन चुके हैं। बीहड़ों के बीच हरी-भरी यह जगह दूर से मन मोह रही है।

सड़कों के बंजर किनारों को कर रहे हरा

महिला थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मोहर सिंह परमार साल 2003 से मुरैना जिले में तैनात, इससे पहले सालों तक श्योपुर जिले में रहे। जहां पदस्थ रहते हैं, वहां बंजर सरकारी जमीन व सड़क किनारों पर पौधारोपण करते हैं। बीते 20 साल में उन्होंने एसपी आफिस, एसपी बंगले, सीएमएचओ स्टोर भवन परिसर में दर्जनों पौधे लगाए हैं। इसके अलावा वीआइपी रोड से आमपुरा की ओर जाने वाली एक किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों ओर 100 से ज्यादा पौधे लगाए हैं, जिनसे से कई 20 फीट तक के पेड़ बन चुके हैं। सड़क के दोनों किनारे हरियाली से शोभित हो गए हैं। महाराज सिंह, पीपल, महुआ, बेल्वपत्र, अर्जुन, पाखर, गूलर, जामुन और शीशम के ही पौधे लगाते हैं, जिन्हें वह उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद से 300-300 रुपए में खरीदकर लाते हैं।

पानी देने वाले बोरों से लौटा रहे धरती को पानी

हर किसान बोर से फसलों की सिंचाई के लिए पानी निकालता है, लेकिन श्योपुर जिले के चिमलका गांव के किसान कर्मवीर सिंह इसका उलट कर रहे हैं। साल 2018 में अपने खेत के सालों पहले सूख चुके बोर में पाइप लगाकर उसके जरिए खेतों में भरे बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना देते हैं। कर्मवीर सिंह की देखादेखी बगडुआ, रायपुरा, जावदेश्वर व कांचरमूली गांव के कई किसानों ने इसी तरह खेतों में भरे बारिश के पानी बंद बोरों के जरिए धरती को पानी वापस लौटाया। बीते चार साल से हर बारिश में यह किसान ऐसा ही करते हैं। इन गांवों में भू-जलस्तर 165 से 170 मीटर तक वह अब 150 से 155 मीटर पर आ गया है। इसका फायदा भी किसानों को हुआ और कई सूख चुके बोर अब फिर से पानी देने लगे हैं।

कृषि विज्ञान केंद्रों में 28 साल से दे रहे सेवाएं: मथुरा में आयोजित वर्ल्ड बायो साइंस कांग्रेस में किया गया सम्मान

डॉ. एसपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

शिवपुरी। संवाददाता

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मप्र) के कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह को हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोजॉजी, फरह, मथुरा (उप्र) में गत दिवस आयोजित चार दिवसीय वर्ल्ड बायो साइंस कांग्रेस-2022 में इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स, बायो टेक्नोलाजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ. सिंह को यह सम्मान विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में 28 वर्षों तक अनवरत सेवा देने के साथ कृषि एवं किसान कल्याण के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया है। डॉ. सिंह पशुपालन एवं डेयरी विषय से संबंधित विशेषज्ञता रखने के साथ गांव-कृषि-किसान, सम-सामयिक विषयों और अन्य कृषि एवं किसानों से जुड़े मुद्दों पर समाचार पत्र-पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि पर किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, सरकारों एवं आमजन में जागरुकता लाने के लिए नियमित रूप से सकारात्मक लेखन से भी जुड़े हैं। उनके अब तक दर्जनों शोध पत्र, सैकड़ों तकनीकी व्यावहारिक लेख विभिन्न शोध जर्नल एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।

राधामोहन और केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर भी कर चुके सम्मान

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह के कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान, महिंद्रा समृद्धि इंडिया अवार्ड-2016 तथा श्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र आउटलुक स्वराज अवार्ड-2020 से तत्कालीन एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री क्रमशः राधा मोहन सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें अपने सेवाकाल में एक दर्जन से अधिक अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। डॉ. सिंह को मिले इस प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े वैज्ञानिकों-कर्मचारियों के अलावा अन्य कृषि वैज्ञानिकों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी है।

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं पर खर्च होगी राशि

नाबार्ड कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने 4368 करोड़ देगी कर्ज

भोपाल। विशेष संवाददाता

भारत सरकार की प्राथमिकता वाली कृषि एवं ग्रामीण विकाय योजनाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,368 करोड़ रुपए बजट का बैंकों के माध्यम से कर्ज देने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना में नावार्ड ने कृषि, शिक्षा, आवास समेत सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए संभावित ऋण देने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। जिससें सबसे अधिक कृषि आधारित संरचना पर फोकस किया है। नवार्ड ने कृषि आधारित योजनाओं के साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) को शामिल किया गया है।

किसानों की आयु दो गुना करने और कृषि आधारित योजनाओं की वृद्धि के लिए पिछले साल की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में नवार्ड ने पोटेंसियल लिंक प्लान (पीएपी) के लिए 8 फीसदी बजट में वृद्धि की है।

कृषि के लिए संभावित ऋण

नावार्ड ने कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन, रखर-खाव के साथ ही कृषि यंत्र पौधरोपण, पशुपालन क्षेत्र में डेयरी विकास, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी एवं सूअर पालन, मस्त्य पालन आदि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 339 करोड़ की संभावित ऋण की कार्य योजना बनाई है। इसी में बैल, बैलगाड़ी समेत संभावित कृषि प्रणाली की योजनाएं शामिल हैं।

कृषि आधारभूत संरचनाएं

नावार्ड ने कृषि आधारभूत संरचनाओं के लिए 356 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। जिसमें भांडारण सुविधाएं, भूमि विकास, भू-संरक्षण एवं वाटरशेड योजना समेत टिशू कल्चर, एग्रो बॉयोटेक्नोलॉजी, बायो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वर्मी कम्पोस्ट आदि शामिल है।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम इंटरप्राइजेस

नवार्ड ने एमसएमई योजना में शिक्षा, आवास, निर्यात ऋण, नवकरणीय ऊर्जा के साथ ही सामाजिक आधारभूत संरचना जिसमें बैंक शाडुमिल हो। इसके लिए 326 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है।

गांवों में तीन घंटे की बिजली कटौती

फसल सूखने से चिंतित हो रहे किसान, पनप रहा गुस्सा

भोपाल। संवाददाता

भोपाल समेत पूरा प्रदेश इन दिनों अघोषित कटौती के दंश से जूझ रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में एक जैसे हाल हैं। गांव में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है तो शहर में ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान हैं। कभी रखर-खाव तो कहीं फाल्ट की वजह से बिजली बंद हो रही है। भोपाल जिले में हर घंटे औसत 30 शिकायत बिजली सप्लाई बंद होने की अप्रैल माह में दर्ज हो रही है। गांव में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान चिंतित हैं कि कहीं पानी नहीं मिलने से उनकी फसल न सूख जाए। किसान लगातार बिजली अफसरों के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। इधर, कंपनी प्रबंधन ने सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली का समय बदल कर रात की बजाय दिन में कर दिया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में दो से तीन घंटे बिजली बंद होती है। अधिकांश समय ट्रिपिंग की वजह से सप्लाई बाधित होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह भी सप्लाई बंद हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को रात्रि में सप्लाई दी जाती है। दो घंटे ही लाइट मिलती है।

सर्वेयर ने पहले गेहूं रिजेक्ट किया फिर पास करने के दो हजार मांगे

एफआइआर दर्ज, अधिकारियों को जानकारी मिली तो चैन ट्रेस की

किसानों से भ्रष्टाचार का खेल उपज पास करने के ले रहे घूस

भोपाल। गेहूं उपार्जन में रुपए लेकर उपज पास करने का बड़ा मामला सामने आया है। भंडारण केंद्र पर सर्वेयर पहले उपज से भरे ट्रक को रिजेक्ट करते और फिर पास करने के लिए संबंधितों से रुपए की मांग करते हैं। एक मामले में ऑनलाइन भुगतान कर चैन ट्रेस करने के बाद चार सर्वेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। समिति द्वारा खरिदी केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरिदा जाता है। बाद में इन्हें भंडारण केंद्रों पर भेजा जाता है।

केंद्रों पर भी भंडारण से पूर्व गेहूं की ग्रेडिंग होती है और यदि इसमें कमी पाई जाती है तो उपज से भरे ट्रक खरिदी केंद्रों को लौटा दिए जाते हैं। गोडाउन पर ग्रेडिंग के लिए आरबी एसोसिएट भोपाल को के सर्वेयर नियुक्त रहते हैं। मामले के अनुसार महादेव पीईजी गोदाम पर आरबी एसोसिएट भोपाल के सर्वेयर अशोक पटेल, धर्मेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल व बलराम द्विवेदी द्वारा लोहाना के खरीदी केंद्र से गेहूं भरकर आए ट्रक को 14 अप्रैल को रिजेक्ट कर दिया। सर्वेयर ने लोहाना के समिति प्रबंधक और कृषक वीरेंद्र यादव से फोन पर चर्चा की और ट्रक पास करने के लिए दो हजार रुपए की मांग की। ऑनलाइन के माध्यम से ट्रक पास करने के एवज में दो हजार रुपए जमा भी करवा लिए गए। अधिकारियों ने मामले में पड़ताल कर चेन ट्रेस की। इसके बाद लोहाना सेवा सहकारी समिति प्रबंधक द्वारा नरवर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

> गोदाउन में उपज से भरा ट्रक रिजेक्ट करने और फिर पास करने के लिए सर्वेयर द्वारा ऑनलाइन दो हजार रुपए लेना सामने आया है। पड़ताल में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधितों के खिलाफ समिति प्रबंधन द्वारा पुलिस प्रकरण दर्ज करवाय गया है। जिले में अन्य जगह भी यदि इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
> - एमएल मारू, जिला आपूर्ति अधिकारी, उज्जैन

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770036925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)